संयोजन, समन्वय से सफलता: कहानियाँ हमारी

Mahatma Gandhi NREGA

Ministry of Rural Development, Govt. of India

प्रदान Pradan

PROFESSIONAL ASSISTANCE FOR DEVELOPMENT ACTION

प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य में गत वर्षो में विकास कार्यक्रमों में समाज – सरकार – बाजार के बीच गठजोड़ करके जमीनी स्तर पर बेहतर काम किये जा रहे है और इस कड़ी में नरेगा के अंतर्गत और उसके माध्यम से हो रहे कार्यो की प्लानिंग प्रक्रियाओ में बदलाव लाकर ये तय किया गया है की कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय को मजदूरी के साथ साथ उनके द्वारा किये जा रहे आजीविका संवर्धन कार्यो में तेजी लाई जा सकती है। वर्तमान के अनुभव प्रोत्साहित कर रहे है और हमारी कोशिश है की इन उदाहरणों से सीख लेते हुए आने वाले वर्षो के लिए एक रुपरेखा सोची जाए और राज्य में उसके अनुसार कार्य आगे बढे।

सूफिया फारूकी वली (आई. ए. एस.),
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् , भोपाल

पिछले कुछ समय में हुए प्रयासों में महिलाओ की नरेगा के अंतर्गत प्लानिंग तैयार करने, बनी कार्य योजनाओ के क्रियान्वन में उनकी अलग अलग भूमिका निभाने के अनुभव देखने में आये हैं और महिलाओ की ऐसी अग्रणीय भागीदारी और भूमिका से मुझे बेहद खुशी हुई है। मैं आशा करती हूँ की आने वाले समय में और बड़ी संख्या में उदाहरण हमे देखने को मिलेंगे।
इस कहानियो के संकलन में शामिल सभी महिलाओ, उनके हजारो साथी सदस्यों, नरेगा कार्य दल टीम सदस्यों को मैं धन्यवाद देती हूँ की उन्होंने अपने अनुभव इस किताब में साँझा किये। राज्य में आने वाले वर्षो के लिए हम प्रयत्न कर रहे है की आजीविका संवर्धन, जल संकट एवं जलवायु परिवर्तन, सेहत और पोषण आदि से सम्बंधित विकास लक्ष्यों में नरेगा कैसे योगदान दे सकता हैं और इसकी कार्यक्रम क्रियान्वन स्तर पर किस प्रकार की रुपरेखा बनायी जाए। इन कार्यो की रूपरेखा बनाने में मिले सहयोग और इस कहानी संग्रह को तैयार करने के लिए प्रदान संस्था को मैं राज्य इकाई की ओर से धन्यवाद देती हूँ। मुझे भरोसा और विश्वाश है की हमे मिल रहे अनुभव और उनपर निरंतर मंथन करते हम एक बड़ी मुहीम राज्य में शुरु कर पायेंगे।

भूमिका

प्रदान संस्था पिछले चार दशकों से मध्य भारत के दूरस्थ आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कार्य कर रही है। हमारा प्रयास रहा है कि सीमांत ग्रामीण समुदाय- मुख्यतः महिलाएँ संगठित होकर अपने सामूहिक प्रयास से लैंगिक,सामाजिक और आर्थिक असमानताओ को पार करके बराबरी और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में अग्रसर रहें। इसके लिए जरूरी है कि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वन में ये ध्यान दिया जाए की समाज के कमजोर और पिछड़े तबके को कैसे अवसर मिल पाए। कहानियों का यह संकलन ऐसे ही अनुभवों की झलक देता है जिनमे मनरेगा और पंचायत राज व्यवस्था के साथ मिलकर सफलतापूर्वक काम करते हुए महिला संगठनों ने अपने सदस्यों की जिन्दगी में एक बदलाव लाया है और निरंतर इस हेतु प्रयासरत है।

मनोज कुमार,
इंटीग्रेटर
प्रदान

सभी गांवों की, सभी संगठनों की और उनके प्रयास से सशक्त सभी महिलाओं का अनुभव एक संकलन में शामिल करना असम्भव है लेकिन आशा है कि ये अनुभव हजारों लाखों परिवारों के लिए प्रेरणा और आशा का स्त्रोत बनेगें । इन सफल अनुभवों को साकार करने में प्रयासरत महिला संगठनों को क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्यो और मनरेगा कार्य-दल का जरूरी सहयोग मिला है अन्यथा ये कभी संभव नहीं हो पाता। मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आशा है कि ये प्रयास और अधिक तेजी और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। इन कहानियों के संकलन को तैयार करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं मेरी टीम के सदस्यो को और साथ में विभिन्न जिला प्रशासन टीम के अगुवाई दल को जिन्होंने फील्ड स्तर के अनुभवों को जानकर कार्यरत टीमों को प्रोत्साहित और मार्गदर्शित किया।

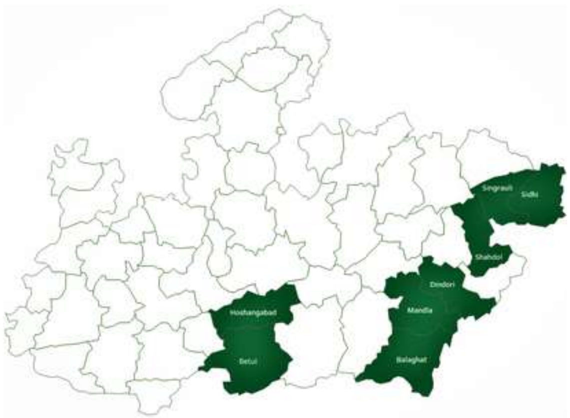

विषयसूची

नेतृत्व की कला सिखाती, विश्वास से भरी कला बाई 06

जैसा नाम वैसा काम – कार पेंटर 08

जब करिया उमरी की बाइयां तानों पर पलट के पूछ "तो?" 12

मैं पंचायत की पहली मेट हूँ ... 14

मैंने साधन से आजीविका संसाधन बढ़ाया 15

कौशल में बढ़ोतरी 16

मनरेगा के प्रति बढ़ता विश्वास 17

"हम तब तक नहीं जीतेंगे जब तक कोई पीछे छूटे हैं" 18

नरेगा से मिला आमदनी का नया ज़रिया 19

अपनी बात बोलने जिला पहुँचीं महिलाएं 20

गैर कानूनी काम पर रोक 21

महिलाओ ने की मनरेगा को लेकर पंचायत के साथ चर्चा 22

जल संवर्धन के कामो को पहली बार ग्राम में प्राथमिकता से करवाया 23

महिलाओ ने अपनाया लम्बी सोच से दीर्घ अवधि वाली आजीविका गतिविधि : फल खेती 24

महिलाओ ने की मनरेगा को लेकर पंचायत के साथ चर्चा 25

ग्राम योजना निर्माण में अन्य योजनाओ को जोड़ सिंचित रकबा बढाकर सब्जी खेती की शुरुवात की 27

पलायन से स्वावलंबन तक - रहंगी रैयत की महिलाओं का सफ़र 28

केंचुआ खाद बनाकर अपनी खेती को सुदृढ करने की पहल 30

अपनाई नई तकनीकी बनायी खुशहाल ज़िन्दगी 31

ठान लोगे तो सबकुछ है मुमकिन 32

महिला संगठन ने साकार की बदलाव की परिकल्पना 34

कुम्हर्रा ग्राम: एकीकृत सोच और अटल इरादे – सफ़र बदलाव की ओर 35

ममता समूह का संकल्प – खुद की पहचान और बेहतर आजीविका 36

धमनपानी – लड़ाई अस्तित्व की 37

सब्जी लगाने से बदली जिन्दगी 38

मछलीं पालन कर बढ़ी आय 39

बर्रा जमीन बन रही उपजाऊ 40

डोंगरिया की कहानी ,बनी जनपद की जुबानी 42

आम का बगीचा - एक नया आशियाना 43

संसाधनो में सुधार हमने किये एक साथ 44

संसाधन सखियाँ 45

ग्राम संघटन की ताकत से गाँव का नियोजन 46

चंद्रकली की कहानी 47

महिला सरपंच 48

नेतृत्व की कला सिखाती, विश्वास से भरी कला बाई

कला बाई नर्मदा महिला संघ , बैतूल फेडरेशन की लीडर है। पिछले एक दशक में, उन्होंने संघ के साथ अपने गाँवो में एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के कार्यो की प्रगति की है। एक फेडरेशन लीडर होने के नाते कला बाई ने ब्लाक प्रशाशन और जिला प्रशाशन के साथ कई बार वार्तालाप करते हुए सामंजस्य बैठाया है। नागरिकता के विचार से कला बाई ने अपने हक़, मौलिक अधिकारो और जिम्मेदारी की समझ बनाई और अपने संघटन के काम और उसके विकास में योगदान दिया। उन्होंने कई बार मर्मादा महिला संघ का राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। नर्मदा महिला संघ आज के दिन में 3000 महिलाओ के साथ काम करता है और अपने क्षेत्र के परिवारों को विकास प्रक्रियाओ में सहयोग देता है। वो हमेशा अपने साथी सदस्यो, पंचायत सदस्यों एवं प्रशाशन सदस्यों को बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।

हर साल, कला बाई संघ के लीडर के साथ ब्लॉक और जिला प्रशासन से मिलती हैं और संघ कि प्रगति, ग्राम विकास का योजना, प्रशासन से संघ कि आवश्यकता के समर्थन को साझा करती है। फेडरेशन की बैठकों में साझा किए जाने पर इन अनुभवों ने महिला समूहों को नागरिकता के विचार के साथ ग्राम पंचायत से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कला बाई, अशिक्षित महिला है, फिर भी वो संसाधन प्रबंधन योजना निर्माण (INRM) की समझ में काफी कुशल है जिसके माध्यम से उन्होंने अनेक गाँवो में महिला समूहों, ग्राम पंचायत, पदाधिकारियों और ग्रामवासीयो की भागीदारी के साथ गाँव में कार्य नियोजन करवाया है और प्रक्रियाओ को सुगम बनाया है। सामाजिक मानचित्र और ट्रांसेक्ट वाक की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाकर एक समग्र ग्राम विकास योजनाएं तैयार की । इन प्रक्रियाओ के द्वारा गाँव में कमजोर और उपेक्षित परिवारों की पहचान की और उनके अधिकारों पे काम किया जिसका परिणाम ये है की लोगो के जीवन में एक गुणात्मक बदलाव आया है।

जैसा नाम वैसा काम - कार पेंटर

लोकेश कारपेंटर, बैतूल जनपद में ऍम.जी.नरेगा के तहत उपयंत्री के पद में है। प्रारंभ में, ऍम.जी.नरेगा के प्रति उनका दृष्टिकोण, संरचनाओं के तकनीकी और बजटीय पहलुओं को सुनिश्चित करने पर केंद्रित था। समय के साथ, नर्मदा महिला संघ के महिला संगठन और प्रदान के साथ उनकी बातचीत ने एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की समझ बनाने में मदद की।

गाँव का विकास, गाँव वासी के योगदान से ही साफल हो सकता है, और महिला संगठन कि भूमिका अपने गाँव के विकास में अहम् समझते हुए, उन्होंने, उनका नजरिया महिला संगठन को हितग्राही कि तरह नहीं, बल्कि, विकास का उत्तरदायित्व के दृष्टिकोण से देखा। यह नज़रिए में बदलाव के कारण, लोकेश जी ने संगठन से चयन किये महिला मेट के साथ काम करना उचित समझा। उनका समझ तकनीकी और बजट के पहलुओ पर बनाया, जिसके द्वारा, महिला मेट ऍम.जी.नरेगा के कार्य को सुचारु रुप से कर सके। इसके अलावा, अपने क्षेत्र में, वह आईएनआरएम के बारे में महिला किसानों और समूहों कि समझ बनाने के लिए के उनके साथ लगातार वार्तालाप करते है, ताकि वो संगठन गुणवत्ता वाले कार्यों की वास्तविकता सुनिश्चित कर पाए ।

अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ाई

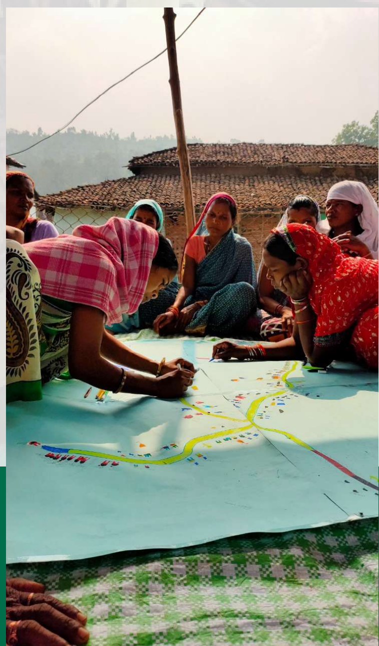

सुगराति बाई, एक 45 वर्षीय निरक्षर (पढ़ने और लिखने में असमर्थ) समूह सदस्य हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश में बैतूल के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के रतनपुर गांव में रहती हैं। इनके पति की मृत्यु 4 साल पहले हो गई थी, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, इस घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया सामाजिक और आर्थिक रूप से। जीवन के ख़राब दौर से गुजरते हुए, समूह सदस्यों ने उसकी कई तरह से मदद की जैसे - उसके राशन के लिए चावल और गेहूं का योगदान, उसे कपड़े और कुछ बर्तन उपलब्ध कराना और एसएचजी से उसके घर के निर्माण के लिए पैसे उधार देना। फिर भी उसके लिए यह पर्याप्त नहीं था कि उसे कुछ तत्काल सफलता की आवश्यकता थी। जब आईएनआरएम योजना गांव में आयोजित बनाई गई तब एक एसएचजी सदस्य होने के नाते उन्होंने पूरी प्रक्रिया में भाग लिया। हालाँकि वह एक बहुत ही सक्रिय SHG सदस्य है, लेकिन उसने अपने लिए कुछ भी योजना नहीं बनाई है और दूसरों के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया है। सुगरतीबाई ने दो अन्य मजदूरों के साथ अपनी क्षमता दिखाई और घोड़ाडोंगरी में खेत तालाब का काम शुरू करने वाली पहली थी। उसने अपने गाँव में तीन अलग-अलग खेत के तालाबों में 60 दिनों तक लगातार काम किया। एसई और ग्राम पंचायत के समर्थन से उन्हें लगभग 16-17 दिनों में अपना वेतन मिल गया, जो उनके लिए डूबती नाव में एक तिनके जैसा सहारा था। पंचायत से समय पर भुगतान प्राप्त करने से उसे अपने ख़राब समय में अपने घरेलू खर्च का प्रबंधन करने में मदद मिली। उनके अनुसार "अगर ये काम नहीं आता तो पता नहीं मैं क्या करती।"

आगे बढ़ते हुए, उन्होंने स्वेच्छा से ग्रामीणों के साथ खरीफ कृषि की योजना बनाने, इनपुट सामग्री की मांगों को मजबूत करने और डीलर के साथ उनके जुड़ाव का प्रभार भी लिया। उसे अपने जीवन को स्थिर बनाने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, जिसमें उसके बच्चों के लिए शिक्षा, एक घर, उसकी कृषि भूमि पर अधिकार और एक स्थिर आजीविका विकल्प शामिल है और ये सभी बुनियादी सुविधाएं उन्हें अब दूर नहीं लगती उनकी ऊर्जा, प्रेरणा ओर उनका एसएचजी साथियों पर विश्वास देखने के बाद।

जब करिया उमरी की बाइयां तानों पर पलट के पूछ "तो?"

बेतुल जिले में एक गाँव करिया उमरी, कोयला खदान के क्षेत्र में आता है, जिस वजह से यहाँ का जल स्तर गाँव वासियों के लिए एक अत्यंत ही चिंताजनक विषय है | यहाँ कि समूहों ने गंभीर रुप से अपने संगठन के माध्यम से गाँव में कुछ बदलाव लाने के ओर मंथन किया| आई.एन.आर.एम् के माध्यम से गाँववासियों ने 4 दिन तक लगातार अपने खेत, जंगल व गाँव घूमे और 44 ऐसे कार्यों का चयन किया जिससे जल स्तर पे तत्काल प्रभाव पड़े |

इन कार्यो का आवेदन लोगों ने ग्राम सभा में पंचायत के पास जमा करवाया | जब पहला लॉकडाउन घोषित हुआ, और आजीविका ठप पड़ने के कारण तो करिया उमरी के लोग चिंतित हो गए | ऐसे में समूह की बाईयो ने गाँव को इस समस्या से निकलने का रस्ता दिखाने का ठान लिया | समूह कि बाईयो ने स्व-आंकलन किये हुए कार्यों की सूची व एक पूरा लेबर लिस्ट तैयार की ताकि वे मनरेगा के माध्यम से गाँव में ही मजदूरी कर अपने खेतों को सुधारें |

परंतु, पंचायत के लोग मजदूरों को एक ही सामुदायिक तालाब जिसमे लगभग 40 लोग काम कर सकते हैं, उसमें काम करने हेतु मजबूर कर रहे थे | ग्राम वासियों द्वारा उस दोहरान बनाई गई लिस्ट लगभग 90 बेरोजगार लोगों को दर्शा रहा था, तथा वह सामुदायिक कार्य गाँव से दूर भी था | ऐसी स्तिथि में बाइयों ने गाँव स्तर पर बैठक बुलवाई, जिसमे सरपंच, सचिव को आमंत्रित कर उनके साथ चिंता किये और उल्लेखता सहित राधा बाई के खेत तालाब का कार्य शुरू करवाए |

इस संघर्ष के पूरे सिलसिले के दौरान, बाइयों का हौसला कई बार डगमगाया, ख़ास तौर पे जब, लोग तानाशाह कर उनको नीचा दिखाते, पर अपनी हिम्मत से, बाइयां हर बार जवाब देती | राधा बाई, को गाँव के प्रभावशाली लोगों ने ताना मार कर "तूने तो जैसे अब पगड़ी ही पहन ली है, सरपंच का चुनाव भी लड़ेगी क्या?", जिस पर राधा बाई ने मुस्कुराते हुए जवाब देती , "तो? आप क्यों परेशान होते हो?" |

मैं पंचायत की पहली मेट हूँ ...

काम को करने के लिए पहला कदम सबसे चुनौतीपूर्वक और ज़िम्मेदारियों से भरा होता है | ऐसी ही एक कहानी है शाहपुर ब्लॉक में बनबेहड़ा ग्राम पंचायत की संतरी बाई की जो अपनी पंचायत में पहली महिला मेट बनी | संतरी बाई गांव के स्वयं साहयता समूह की सदस्य है और इस अवसर के साथ वह गांव की महिला प्रतिनिधि के रूप में आगे आयी है जो अपने आप में काफ़ी चुनौती से भरा काम है क्योकि प्रतिनिधित्वता आज भी पुरुष-प्रधान क्षेत्र है |

उनके इन्ही प्रयासों के कारण गांव में और महिला मेट को नियुक्त करने की बात चल रही है | वह स्वयं मेट की भूमिका के कारण अपने निजी जीवन में आये परिवर्तन को स्वीकार करती है और कहती है कि इससे पहले वह अपने गांव के बाहर शायद ही लोगो को अच्छी तरह से जानती थी और अब उनके काम के कारण, उनका संपर्क गांव से ज्यादा बढ़ गया है।

मैंने साधन से आजीविका संसाधन बढ़ाया

मनरेगा ने इस महामारी में सभी की ओर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन इस योजना का सभी तक पहुंच पाना एक अलग चुनौती भी रहा है । नरेगा के तहत जिला प्रशासन और महिला समूहों के बीच सहयोग बनाने के लिए प्रदान एक प्रमुख भागीदार रहा है।

बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक में महिला समूह कुक्कुट पालन में रुचि रखते है और नियमित रुप से सामूहिक और ग्राम पंचायत के साथ चर्चा के माध्यम से गतिविधि में शामिल होने के रास्ते तलाशते है। छिमडी में महिला समूहों ने वैकल्पिक आजीविका गतिविधि के रुप में मुर्गी पालन को चुनने का फैसला किया। आशा बाई छिमडी गांव में चांदनी महिला समिति की सदस्य हैं। कुक्कुट पालन गतिविधि शुरु करने के प्रयास में उन्होंने शेड निर्माण के लिए पंचायत से संपर्क किया। ग्राम पंचायत के सहयोग के साथ मनरेगा के माध्यम से 1 लाख रुपये जुटाकर पोल्ट्री शेड का सफलतापूर्वक निर्माण किया गया। वर्तमान में वह 438 चूज़ों को पाल रही है और उसने दो चरण में 7500 रुपये कमाए हैं। वह सालाना 5-6 चरण ले सकती है ।

कौशल में बढ़ोतरी

शाहपुर जनपद में मनरेगा के काम के समय लोग और पंचायत के द्वारा काम की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता था। रोज़गार साहयक या मेट के कहे अनुसार काम करने का प्रचलन था । शाहपुर ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों में जो क्षमता वर्धन का काम हुआ है और महिला समूह सदस्यों के समर्थन से समुदाय संरचनाओं को अधिक उत्पादक बनाने के लिए अब लोग सही तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। कई ग्राम पंचायतों में, जी आर एस, सचिव और मेट भी इन कौशलों को सीख रहे है जो उनके लिए नए है, और वे ब्लॉक में योजना निर्माण हेतु सहयोगी संस्था प्रदान द्वारा किये जा रहे प्रयासों को स्वीकार रहे है।

मनरेगा के प्रति बढ़ता विश्वास

"हम मनरेगा में काम नहीं करेंगे" से लेकर 100 दिन मनरेगा में रोजगार प्राप्ति की पहावाड़ी गाँव के लोगो की यात्रा दिलचस्प रही है। जब पहली बार गाँव में मीटिंग करके 3 साल का मनरेगा योजना बनाने का ग्राम संगठन के सामने प्रस्ताव रखा तो ग्राम संगठन ने भीषण विरोध किया। "हम पंचायत के साथ काम नहीं करेंगे, चाहे हमें ईंट भट्टी में कम पैसा मिलता है पर मिलता तो है!" लोगो में पुराना पेमेंट न होने का गुस्सा काफी था और पंचायत से विश्वास उठ गया था।

निरंतर मीटिंग और प्रयास के बाद एक नरेगा साथी का चयन किया गया और पहली बार लेबर डिमांड भरा गया, जिन मजदूरों के जॉब कार्ड में गलतियाँ थी, उनका सुधार किया गया जिससे पेमेंट में देरी न हो। पंचायत अधिकारियो ने भी ग्राम संगठन में बैठ कर बाइयों के साथ मनरेगा के मुद्दे पर बात की और परेशानियों का समाधान निकालने का प्रयत्न किया। इन्ही सभी कोशिशो से आज के दिन में पहावाड़ीगाँव में औसत कार्य दिवस 63 हैं, जो की पिछले साल 30 थे। कई लोगो ने 100 दिन का रोजगार मनरेगा से लिया है। गाँव के मजदूर जो पहले ईंट भट्टी में कम पैसे में काम करते थे, आज उनमे से कुछ ने ईंट भट्टी का काम छोड़ कर मनरेगा को खेती के अलवा अपनी आय का मुख्य स्त्रोत भी बनाया है।

“हम तब तक नहीं जीतेंगे जब तक कोई पीछे छूटे हैं”

मूढा के ग्राम संगठन ने एक सनोति बाई की शारीरिक रूप से विकलांगता देखते हुए और नरेगा कार्यों की समझ पकड़कर उनके लिए काम तय किया। अभी तक वह मनरेगा में काम करने में असमर्थ रहीं थीं। योजना क्रियान्वन के नए बदलावों में जब शाहपुर के मूढा गाँव में उनकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद से उन्होंने मनरेगा योजना के अंतर्गत होने वाले कामों में कार्यस्थल पर पानी पिलाने का काम किया। यह इस गाँव का पहला ऐसा वाकया था जिसमें विकलांगता रोजगार के बीच नहीं आई थी। इस प्रक्रिया में सनोति बाई ने इस योजना के माध्यम से अपने खेत में मेड बंधान का काम भी लिया है।

नरेगा से मिला आमदनी का नया ज़रिया

एक साल पहले तक बिझारATोला में बरसात में धान खेती के अलावा कुछ विशेष विकल्प नहीं थे| सिंचाई साधन ना होने के कारण खेती के अलावा और कोई आजीविका का साधन भी नहीं था । अनारकली का मछली पालन का निर्णय एक विकल्प के रूप में उभरा है । ग्राम विकास योजना के दौरान मीनाक्षी तालाब का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन करवाया गया । मनरेगा सखी, मेट और इंजीनियर के साथ मिलकर तालाब निर्माण का कार्य पूरा हुआ। शहडोल और बांधसागर से बीज लाकर, तालाब में अब मछली पालन शुरू भी हो गया है। इन्हें देख गाँव के दो और परिवार प्रोत्साहित हुए है, और एक परिवार ने मीनाक्षी तालाब का योजना पंचायत में जमा भी कर दिया है।

अपनी बात बोलने जिला पहुँची महिलाएं

ढ़ेढुआ में समुदाय और पंचायत कभी साथ नहीं आए और यही कारण था के पिछले कुछ वर्षों से यहाँ मनरेगा के काम नहीं हुए। ग्राम विकास योजना के दौरान जल और ज़मीन सम्बंधित कार्यों की योजना बनी परन्तु बहुत प्रयास के बाद भी पंचायत ने योजनाएं स्वीकृत नहीं की । महिलाओं ने मिलकर ग्राम सभा का आयोजन किया लेकिन वहां भी पंचायत सहकर्मी नहीं पहुंचे । जब जनपद में भी बात नहीं सुनी गयी, तो महिलाएं ज़िला कार्यालय पहुंचीं। कई मशक़्क़त के बाद आज गाँव में मनरेगा के तहत 3.73 लाख रु का काम चल रहा है जैसे के तालाब व खेत निर्माण। पंचायत अब समुदाय से चर्चा में रहता है और लेबर के लिए एक महिला मेट का चयन भी हुआ है।

गैर कानूनी काम पर रोक

तगावर में ग्राम विकास योजना और उसके तहत हुई हक़ और अधिकार की ट्रेनिंग रंग लायी। गाँव में JCB द्वारा जब काम चालू हुआ तो समूह की महिलाओं ने मिल कर इस पर रोक लगाया। इसी बात को महिलायें पंचायत में ले कर गयीं परंतु वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। परेशान हो कर ग्राम कि महिलाओं ने साथ मिलकर अपने पंचायत में हो रहे गैर कानूनी काम की शिकायत जनपद तक पहुंचाई। इस घटना को स्थानीय समाचार में भी प्रसारित किया गया । जनपद सी०ई०ओ० ने तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए सही कार्यवाही करने का निर्देश दिया। यह तगावर के महिलाओं कि साझा पहल थी जिससे आज गाँव में सभी काम मज़दूरों द्वारा होते है जिसका देख रेख ग्रामवासियों द्वारा चयनित महिला मेट करती है।

महिलाओ ने की मनरेगा को लेकर पंचायत के साथ चर्चा

महिलाओं द्वारा बुलायी गयी ग्राम सभा में लोगों ने पंचायत से मनरेगा को लेकर कई सवाल किए। मानदेय से लेकर काम खुलवाने, काम का स्वीकृत राशि और मानव दिवस पर चर्चा हुई। इसी बीच लोलि सिंह ने अपने खेत में अधूरे भूमि शिल्पी कार्ययोजना को लेकर सवाल किए तो पंचायत ने कहा की केवल 75000 रुपय स्वीकृत हुए थे जो की इस्तेमाल हो चुका है। पंचायत में मौजूद मास्टर रोल देखा गया तो स्वीकृत राशि और बतायी जा रही राशि में अंतर पाया गया। जिस काम को राशि खत्म होने के कारण छोड़ दिया गया था उसे दोबारा शुरु करने का निर्णय हुआ। इसी प्रकार के अन्य चर्चाओं के बाद पंचायत ने समुदाय से माफ़ी माँगी और आगे काम को समुदाय के साथ मिलकर करने का निर्णय लिया।

जल संवर्धन के कामो को पहली बार ग्राम में प्राथमिकता से करवाया

पिपरखाड गाँव मे पहले पंचायत द्वारा ज्यादातर मेड बंधन का कार्य किया जाता था, जिसमे अब महिलाओ ने योजना निर्माण में ध्यान दिया की अब जमीन की बनावट के अनुसार कार्य प्रसातवित किए जाए। पूछने पर दीदी लोग बताते हैं की कंटूर ट्रेंच एक ऊपरी बंजर जमीन कंटूर लाइन पर किए जाने वाली ऐक्टिविटी है जो मिट्टी के कटाव को कम करती है तथा बारिश के पानी को धीमा करके नीचे जाने देता है जिससे निचली जमीन मे जलाशयों का जल स्तर मे बढ़ावा होता है | उन्ही मे एक कंटूर ट्रेंच का कार्य किया गया जिसमे , 8 एकड़ की बंजर भूमि को कटाव से बचाया गया, तथा 5 समूह की दीदी लोगों ने इसमें काम किया।

महिलाओ ने अपनाया लम्बी सोच से दीर्घ अवधी वाली आजीविका गतिविधि : फल खेती

फलदार पौधे के बारे मे पूरे ब्लॉक मे पहले सार्वजनिक जमीन मे होता था जो कभी सफल नहीं हुआ था। जब समूह की दीदी तथा प्रदान टीम के प्रयासों से समुदाय हितग्राही मूलक फलदार पौधे के लिए भी सहमत होने लगे है तथा आज की तारीख मे 150 से ज्यादा किसानों ने फलदर पौधे लगा चुके है जो निरंतर और आगे आवेदन आने की संभावना है।

फल दार पौधे एक महत्वपूर्ण आजीविका संवर्धन और पर्यावरण अनुकूलता के हिसाब से किया जा रहा है, ये तीन साल बाद किसान दीदियो का स्थायी आजीविका का साधन हो जाएगा साथ मे उसी खेत मे अन्य फसल उगा कर दोहरा फायदा कमाया जाएगा पौधे से शुरुवात में किसान को 1000 रुपये/प्रति पौधे का मुनाफा होगा। आज गाँव में ब्लाक में सभी प्रशिक्षित दीदियो की ये समझ हैं की फलदार पौधे की ऐसी किस्मे है जो तीन से चार साल बाद फल देने लगते है और नरेगा में इसके अन्दर 100-250-300 पौधे लगाने का प्रावधान है जो एक लाइन से होगा जिसमे खाद, कीटनाशक, निराई गुड़ाई, फेन्सिंग आदि का सहयोग परियोजना मे है।

30x40 संरंचना - एक नयी पहल

मनरेगा कार्यक्रम अंतर्गत 30X40 संरचना की एक नयी पहल डिंडौरी जिले के अमरपुर विकासखंड के मोहन्झिर मॉल ग्राम में समूह की महिलाओं ने की है। यह संरचना 5-10 % ढाल वाली ज़मीन के लिए एकदम उपयुक्त है। इस संरचना के विषय में समूह की महिलाओं ने अपने गाँव की तीन वर्ष की योजना बनाते समय प्रदान संस्था द्वारा जाना था और इसके पश्चात् क्षेत्र भ्रमण कर इस ढाल की ज़मीन के लिए महिलाओं ने इस संरचना को योजना में प्रस्तावित करवाया था। इस संरचना का उद्देश्य मिटटी के कटाव को रोकना और ज़मीन के भूजल स्तर को बढ़ाना है जिससे कृषक न केवल इस ज़मीन पर कुछ फसल ले सके और साथ ही साथ वृक्षारोपण कर अतिरिक्त लाभ कम सके।

इस संरचना को महिलाओं ने विडियो में तो देखा था परन्तु अपनी आँखों से अपने समक्ष नहीं देखा था। इसके लिए मोहन्झिर मॉल के अर्चना समूह के गुलबसिया और राजकुमारी और उगता सूरज के कुम्हारिन और कलरिन बाई जिनके 06 एकड़ के खेत में यह गतिविधि होना था बाकी गाँव की महिलाओं के साथ लुटगाँव ग्राम भ्रमण के लिए गये और संरचना की बारीकियो को समझा और अपने ग्राम वापस लौटकर दस्तावेज इकट्ठा कर फाइल बनाकर पंचायत में जमा किये जहाँ से वह जनपद आये और उनका कार्य पारित हो गया और फिर उनके खेतों में कार्य प्रारंभ हुआ जिसमे प्रदान संस्था द्वारा उनको तकनीकी जानकारी दी गयी और पंचायत के रोज़गार सहायक और मेट को भी इस संरचना को ज़मीन पर उतरने का प्रशिक्षण दिया गया। इस पूरे कार्य की निगरानी समूह की महिलाओं ने अपने संगठन स्तर से परियोजना क्रियान्वयन समिति को चुनकर उसके माध्यम से की और अभी वृक्षारोपण के लिए भी फाइल तैयार कर पंचायत में जमा की है।

ग्राम योजना निर्माण में अन्य योजनाओ को जोड़ सिंचित रकबा बढाकर सब्जी खेती की शुरूवात की

डिंडौरी जिला जहाँ सिंचित भूमि मात्र 10 प्रतिशत से भी कम है जबकि औसत वार्षिक वर्षा 1350 mm है, ऐसे में जरूरी था की जल संग्रहण के साथ साथ जल उठाने के कार्य भी साथ में हो। इसको ध्यान में रखकर झम्री बाई वन-ग्राम झरना घुघरी से और गिरनिया और सेवकली बाई वनग्राम जैतपुरी ने तय किया की वह अपने खेत में बने कुएं के लिए मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना से जोड़ेंगी। इसके लिए उन्होंने ग्राम में निर्मित योजना अनुसार पहले रजिस्ट्रेशन कराया और 5000 रुपये जमा किये और फिर उनका नाम आने पर उन्होंने बाकी के 20000 रुपये जमा कर अपने अपने खेतों में कुएं में 02 एच पी के पनडुब्बी पंप लगवाए। इसके लिए जैतपुरी की महिलाओं ने अपने महिला संघ से 20000-20000 रुपये ऋण भी लिया जिसका नियमित भुगतान समूह कर रहे हैं। अब जहाँ झम्री बाई टमाटर, बैंगन, तरबूज़ की खेती कर रही है 01 एकड़ ज़मीन पर वहीं गिरनिया बाई और सेवकली बाई भी सब्जी उत्पादन के लिए तैयारी कर रही है।

पलायन से स्वावलंबन तक - रहंगी रैयत की महिलाओं का सफ़र

दो वर्ष पूर्व रहंगी रैयत गाँव के अधिकतर लोग पलायन करते थे क्योंकि उनके पास स्वयं की ज़मीन नहीं थी और वह अधिया पर खेती करते है। समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत रहंगी रैयत ग्राम की इंद्रा गांधी और द्रोपती समूह की महिलाओं ने यह निर्णय लिया की अब वह पलायन पर काम करने नहीं जायेंगे और अपने बाड़ी ज़मीन में ही सब्जी का उत्पादन करेंगे और इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था उन्होंने स्वयं से डीजल पंप लेकर दनदना नाला से पानी खींचकर अपनी बाड़ी तक पहुचाया और टमाटर, बैंगन, आलू, गोभी जैसी सब्जियां लगाना शुरु की।

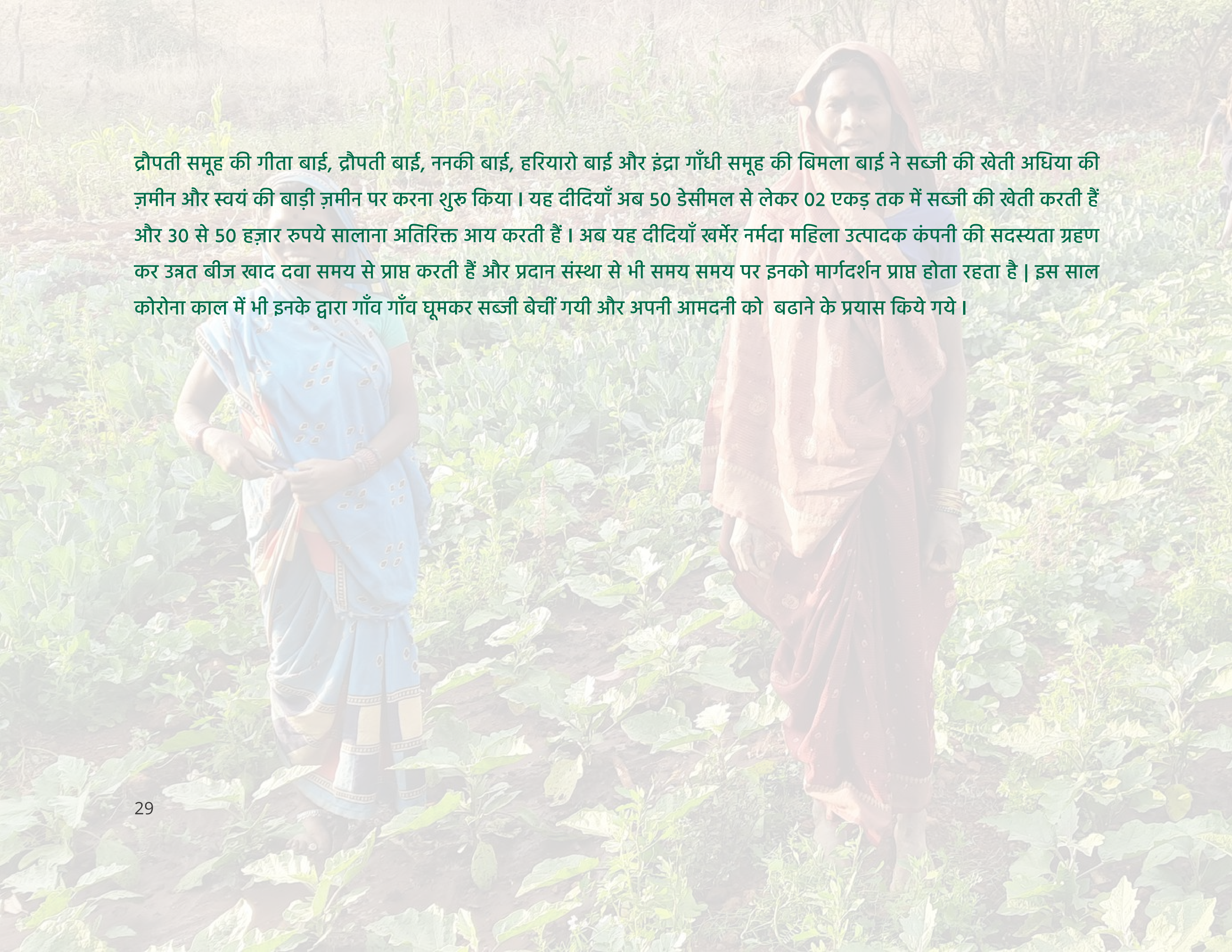

द्रौपती समूह की गीता बाई, द्रौपती बाई, ननकी बाई, हरियारो बाई और इंद्रा गाँधी समूह की बिमला बाई ने सब्जी की खेती अधिया की ज़मीन और स्वयं की बाड़ी ज़मीन पर करना शुरु किया। यह दीदियाँ अब 50 डेसीमल से लेकर 02 एकड़ तक में सब्जी की खेती करती हैं और 30 से 50 हज़ार रुपये सालाना अतिरिक्त आय करती हैं। अब यह दीदियाँ खर्मेर नर्मदा महिला उत्पादक कंपनी की सदस्यता ग्रहण कर उन्नत बीज खाद दवा समय से प्राप्त करती हैं और प्रदान संस्था से भी समय समय पर इनको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है | इस साल कोरोना काल में भी इनके द्वारा गाँव गाँव घूमकर सब्जी बेचीं गयी और अपनी आमदनी को बढाने के प्रयास किये गये।

केंचुआ खाद बनाकर अपनी खेती को सुदृढ करने की पहल

जहाँ एक ओर खाद महंगी होती जा रही है और उसका समय पर मिलना प्रति वर्ष बहुत ही मुश्किल होता है और साथ ही इसके दुष्परिणाम न केवल ज़मीन में पर मनुष्यों में साफ़ तौर पर देखे जाते हैं ऐसे में डिंडोरी जिला के अमरपुर विकासखंड के भाखा मॉल ग्राम के समूह की महिलाओं ने यह तय किया की वह स्वयं की बाड़ी में केंचुआ खाद बनाने के लिए पिट तैयार करेंगे । इसके लिए उन्होंने सीऍफ़टी- मनरेगा कार्यक्रम अंतर्गत वर्मी टांका बनाने के लये 33 महिलाओं ने आवेदन किया और पंचायत में स्वीकृत कराने के पश्चात् टांका बनाने का कार्य प्रारंभ किया और 1 से डेढ़ हफ्ते के अन्दर सभी दीदियों ने टाँके बनाकर तैयार कर लिए| इसके लिए लगभग 15500रुपये का खर्चा आया और 13*8*2.5 घन फिट का टांका बनकर तैयार हुआ। इसके पश्चात महिलाओं ने प्रदान संस्था और कृषि विभाग के कर्मचारियों को केचुआ खाद बनाने क प्रशिक्षण देने के लिए बुलवाया और इसे जुडी सभी तकनिकी बारीकियां सीखी। अब ये सभी महिलायें अपने अपने टाँके में केंचुआ खाद बनाकर अपने खेत और बाड़ी में डालने की योजना बनाकर इससे लाभ लेना शुरु करने जा रही हैं। इसमें उन्होंने यह भी तय किया है की वो आगे चलकर न केवल खाद बनाकर इस्तेमाल करेंगी बल्कि केचुओं को बेचकर भी आमदनी करेंगी।

अपनाई नई तकनीकी बनायी ख़ुशल ज़िंदेगी

अक्सर यह देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन की प्रबंध के अभाव से गरीब परिवारों की आजीविका में बढोतरी नही हो पाती है ऐसे ही परिस्थिति रही ग्राम गारकामट्टा की जो कि करंजिया विकासखंड का एक आदिवासी बहुल्य गाव है । यहाँ पर नर्मदा नदी की पानी साल भर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध तो रहता है परन्तु किसान उसका सही मात्रा में लाभ नही उठा पाते थे ।

ग्राम की प्रमुख महिला लीडर शारदा आजीविका स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष ममता पडवार के दृढ़ निश्चय से ग्राम में लिफ्ट-इरीगेशन कार्य को करके और कुल 10 किसानो के शत प्रतिशत श्रमदान से विद्युत पम्प द्वारा नर्मदा नदी का पानी उपयोग कर कुल 70 एकड़ में सिचाई हो रही हैं । संसाधन निर्भर योजना करते हुए और मिले मार्गदर्शन से ग्राम सभा में अपनी बात रखते हुए उन्होंने किसानों को तैयार किया और दिन-रात मेहनत करते हुए एक महीने के अन्दर लिफ्ट-इरीगेशन को ग्राम में स्थापित किए । सभी किसान एक लाख रुपए से अधिक की आमदनी अब कर पा रहे हैं । वो कहती हैं की ऐसे लघु लिफ्ट सिंचाई कार्यो का आदिवासी ग्रामीण अंचलो में किये जाने की काफी सम्भावनाये हैं जिसको समूह स्वयं से संभाल और आर्थिक योगदान के साथ कर सकते हैं ।

ठान लोगे तो सबकुछ है मुमकिन

एक समय था जब महिलाएँ केवल मनरेगा में मजदूरी करने जाती थी, चुपचाप अपना काम करके वापस आ जाती थी। भुगतान पूरा मिला नहीं मिला, 100 दिन काम मिले ना मिले, जॉब कार्ड में हाजरी भरना और मनरेगा ऍम.आई.एस में उपस्थिति डाली हैं या नहीं, इसकी ना तो कोई समझ थी और न ही कोई सवाल करती थीं। लेकिन समय के साथ महिलाएँ समूह में जुड़कर न केवल इन समस्याओं पे चर्चा कर रही हैं बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ भी रही हैं। इसका एक उदाहरण ग्राम गारकामट्टा का महिला ग्राम संगठन है इन महिलाओं ने बचत-उधार के अलावा कभी दुसरे सामाजिक मुद्दों तथा अपने अधिकारों के ऊपर चर्चा नही की। लेकिन 2019 में इस संगठन ने जल एवं मिट्टी संसाधन के ऊपर चर्चा करते हुए अपने ग्राम के संसाधन मानचित्र, सामाजिक मानचित्र तथा खेत भ्रमण करके योजना तैयार किए।

इस योजना को ग्राम सभा में पारित करने के बाद सरपंच एवं इंजीनियर के साथ मिलकर संगठन की महिलाओं ने मेढ़ बंधान, खेत समतलीकरण, लघु तालाब तथा खेत तालाब की 22 फाइलें जमा किये । टी.एस० और ए.एस० होने के बाद प्राथिमिकता देते हुए, मेट तय करके काम की मांग की और ग्राम के अधिकतम सारे मज़दूरों को 100 दिन का रोजगार मिल पाया। बनी योजना में से 80% कार्य पुरे किये जा चुके हैं।

“इस पुरुष-प्रधान समाज में शिक्षा एवं आज़ादी से वंछित इन महिलाओं ने कई ताने सुनते हुए हार नहीं मानी । इनका मानना है कि ठान लेने के बाद हर काम हासिल कर सकते है”

महिला संगठन ने साकार की बदलाव की परिकल्पना

मंडला जिले के मोहगांव ब्लॉक जो आदिवासी बहूल क्षेत्र है, में स्वयं सहायता समूहों में सम्मिलित महिलाएं मिलकर विकास की नयी इबारत लिख रहीं है। अपना विकासनामा लिख रही इन दीदियों ने अपनी समझदारी, तालमेल एवं मेहनत से अपने गाँव की तस्वीर बदलने की दिशा में एक ज़रूरी कदम बढ़ाया है। यूँ तो ऐसे बदलाव की परिकल्पना आम तौर पर हर ग्रामवासी की चाहत होती है पर इसे धरातल पर उतारने का साहस सिंगारपुर ग्राम की महिला स्वयं सहायता समूहों ने किया है। इस कथन को इसलिए सार्थक माना जा सकता है क्यूंकि ग्राम सिंगारपुर में आम तौर पर खाली पड़े रहने वाली सार्वजनिक ज़मीनों पर इस वर्ष दीदियों ने 15 एकड़ के भूभाग में फलदार पौधारोपण एवं सब्जियों के खेती के शुरु की है। इस सोच को सफल बनाने के लिए गाँव की दीदियाँ, ग्राम प्रतिनिधि, जनपद प्रशाशन एवं प्रदान संस्था ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अदा की है।

कुम्हर्रा ग्राम: एकीकृत सोच और अटल इरादे – सफ़र बदलाव की ओर

निरंतर संघर्ष, एकीकृत सोच से प्रगतिशील ग्राम: “सफ़र में बढ़ते कदम और बदलता हुआ गाँव” गत 7 वर्षो से ग्राम कुमर्राह के लोग महिला समूह सदस्यों की अगुवाई में अपने ग्राम की प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना बनाते हुए क्रियान्वन कर रहे है, अपने ग्राम के अनुभवों को याद करते हुए ग्राम प्रतिनिधि रामवती दीदी बताती है की उन्हें काफी समय लगा लोगो के अन्दर ये नजरिया और समझ बनाने में और साथ ही पंचायत सदस्यों और प्रशाशन के कर्मचारी और अधिकारियो से संसाधन निर्माण के कामो को प्राथमिकता और सहभागी तरीको से करने की बातचीत भी निरंतर की गई।

ग्राम में 40 एकड़ भूमि में कंटूर कार्य, 25 एकड़ भूमि में कृषि-वानिकी और कृषि-उद्ध्यानिकी के तरीको से वृक्षारोपण कार्य हो चुके है, अन्य आजीविका के लिए लाभदायक संसाधनों में मुर्गी शेड और बकरी शेड कार्य के साथ कुल 55 एकड़ भूमि को सिंचित बनाकर गेहूं की खेती शुरु कर दी है। इन सब कार्यो को करते हुए पिछले तीन वर्षो से गाँव ब्लाक में सबसे अधिक लेबर बजट उपयोग हो रहा है।

सफलता के सूत्र : सहभागी चर्चा : परस्पर समन्वय : दूरगामी सोच

ममता समूह का संकल्प – खुद की पहचान और बेहतर आजीविका

मंडला जिले के मोहगांव ब्लॉक के सिलघिटी ग्राम में ममता समूह के दीदियों ने अपने ज़िन्दगी को बदलने की दिशा में अत्यंत निर्णायक कदम उठाया है। ग्राम में करीबन पंद्रह एकड़ सार्वजनिक ज़मीन बंजर भूमि में तब्दील हो चुकी थी जिसकी बिगड़ती स्तिथि पर किसी की भी नज़र नहीं पड रही थी। जंगल पर अत्यंत निर्भरता रहने के बावजूद भी इतने बड़े भूभाग के तरफ ग्रामवासियों की रुची नहीं दिखाई पड़ती थी।तभी ममता समूह के दीदियों ने आपसी सहमति से इस बंज़र पड़े भूमि को बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया। बंजर पड़े भूमि को जीवित करने के दिशा में टिकरी ज़मीनों पर कंटूर के काम किये गए जिसके उपरान्त उनमे खमेर, करंज, आंवला, आम, नीम एवं शीशम के पौधे लगाए गए। पौधों को मवेशियों से बचाने के लिए कैटल प्रूफ ट्रेंच का भी काम करवाया गया।सबसे जरूरी, ममता समूह के दीदियों ने अपने लगाये गए पौधों को बीस सालों तक बचाव एवं निगरानी करने की ज़िम्मेदारी भी उठायी है जो भविष्य में इनकी आजीविका को और मज़बूती प्रदान करेंगे।

धमनपानी - लड़ाई अस्तित्व की

मोहगांव ब्लॉक में कालापानी के नाम से पहचान थी धमनपानी गांव की लेकिन आज यह गांव अपनी एक नई पहचान बना रहा है । गांव के बदलाव की पहल गांव के महिला समूह संगठनों ने की और इसका जरिया था नरेगा कानून के क्रियान्वयन के तरीके में बदलाव लाना। गांव के महिला समुह और बदलाव की सोच रखने वाले पुरुषों ने श्रमदान कर के अपने गांव के विकास की नींव रखी। नये मेट का चुनाव, महिलाओं की ग्रामसभा में सक्रिय भागीदारी, सामाजिक परंपराओं के बंधनों को तोड़ना, युवाशक्ती का सहयोग, इससे गांव के विकास का रास्ता आसान बना । जमीन और पानी के कामों से गांव का जलस्तर बढ़ा। डबरी और जलकुंड जैसे कामों से पानी की उपलब्धता बढ़ी। आजीविका बढ़ाने के लिए सब्जी की खेती, उन्नत धान के तरीके और पौधरोपण जैसी गतिविधियों को बढ़ाया जा रहा है । कालेपानी के अंधेरे से एक नए सूरज की रोशनी अब आकार ले रही है। पंचायत ने अपनी जिम्मेदारी समझ कर गांव को प्रोत्साहित किया अब यह गांव कहता है कि -

"ना कभी पैर थके, ना कभी हिंमत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का इसलिए सफर जारी है..."

सब्जी लगाने से बदली जिन्दगी

जुझारी हमेशा से धान और मक्का की खेती वाला क्षेत्र रहा है, जहां खरीफ में कोदो-कुटकी बोने के लिए जमीन का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि रबी में वे गेहूं एवं चना लगाते थे। यह उत्पाद भी उनके दैनिक आहार का हिस्सा था। सब्जियां कभी प्राथमिकता नहीं थीं और आमतौर पर तब खरीदी जाती थीं जब परिवारों के पास पैसे होते थे। जुझारी में पोषण और संतुलित आहार के महत्व के बारे में गहन हस्तक्षेप भी किए गए।

जुझारी में लगभग 15 लोग साथ आए और अपने क्षेत्र के सामुदायिक सेवा प्रदाता गोमती की मदद से उन्होंने अपनी जमीन के एक हिस्से में सब्जियों की खेती करने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवारों को आश्वस्त किया, उन्हें फसल से आय का वादा किया और अपने घर की जमीन के केवल एक छोटे से हिस्से का उपयोग करके, बाकी में अपनी नियमित खेती जारी रखी। गोमती, जिनके पास एक नर्सरी भी है, ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को टमाटर, बैगन, पत्तागोभी के पौधे और भिंडी जैसी अन्य सब्जियों के लिए बीज मिल सकें। वह हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही । सब्जी से होने वाली आमदनी को देखकर घर के पुरुष कृषि और बिक्री दोनों में सहयोग करने लगे। जुझारी में सब्जियों की खेती में रुचि बढ़ी है और अधिक लोगों ने गर्मियों के बाद सब्जियों की खेती के लिए आगे आये है ।

मछली पालन कर बढ़ी आय

नारायणगंज विकासखंड के चिरी गांव के हेमंत के खेत में तालाब खोदा गया था। अब तालाब में पानी होने के कारण वह 12 एकड़ भूमि पर खेती करने में सक्षम है, जो सामान्य से अधिक है। फिश स्पॉन में प्रारंभिक निवेश के परिणामस्वरुप अब 6 लाख रुपये की वार्षिक आय हुई है। वह साल में करीब 50 से 60 क्विंटल मछली बेचते हैं। जबकि कुछ मछलियाँ चिरी में ही बेची जाती हैं,आजीविका गतिविधि के रुप में मछली पकड़ने की शुरुआत के साथ, हेमंत की आय में लगभग 90% की वृद्धि हुई है।

हेमंत मछली पालन को भी सुरक्षा कवच मानते हैं। जब भी उसे पैसे की तत्काल आवश्यकता होती है, वह हर बार मछली बेचने में सक्षम है। अपनी आय को और बढ़ाने के लिए, वह अब अन्य संभावित मछली पालकों को मछली के अंडे बेचने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश बाहर से अधिक कीमत पर कम गुणवत्ता वाले अंडे खरीदते हैं।

बर्रा जमीन बन रही उपजाऊ

नारायणगंज विकासखंड के बीजेगांव पंचायत के खमरिया गांव में जमीन का एक बड़ा हिस्सा बंजर होने के कारण नियमित खेती करना ग्रामीणों के लिए हमेशा से एक दूर का सपना रहा है. खमरिया की महिला समूहों द्वारा मिट्टी और जल संरक्षण के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना से निकले कार्यों से खमरिया में कुल 11.67 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण के साथ 30-40 मॉडल कार्य पूर्ण हो गया है। फल वृक्षारोपण के साथ-साथ 30-40 मॉडल के वर्तमान उपचार का उद्देश्य पानी के रिसाव को सुनिश्चित करना और भूमि की नमी को बढ़ाना है, साथ ही इस उम्मीद के साथ मिट्टी के कटाव को भी रोकना है कि लोग अब हर साल उस पर खाद्यान्न उगा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, फलों के बागवान किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में काम करेंगे । 2913 आम के पौधे लगाए गए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान फलों के पौधों के बीच में सब्जियां या राहर दाल की खेती कर सकें।

डोंगरिया की कहानी, बनी जनपद की जुबानी

ग्राम डोंगरिया में वर्षो से बंज़र पड़ी हुई जमीन व उसके समीप स्थिति नाला जो कि अनुपयोगी थे मिटटी के जमाव व घास फूस के उगने की वजह से । ये सुधार तब सम्भव हो पाया जब समूह की दीदियों ने इस नाले की समस्या को INRM योजना के माध्यम से ग्राम पंचायत व ब्लॉक तक पहुचाया। ब्लॉक की टीम ने उस क्षेत्र (नाले व जमीन) का गांव की दीदियों के साथ निरीक्षण किया और वहाँ पे नालें के सुधारीकरण का कार्य शुरु किया गया। मनरेगा के माध्यम से नाले में सफाई कि गई। नाले के समीप जमीन के जल स्तर को बढ़ाने हेतु चेक डैम का निर्माण किया गया। जल स्तर को बढ़ाने हेतु उस नाले की पास की जमीन में 3 लघु तालाबो का भी निर्माण किया गया, अब वहां नाले में पूरे साल खेती योग्य जल स्तर बरकरार रहता हैं। मत्स्य पालन का कार्य आज उनकी आजीविका का एक हिस्सा बन चुका है। गाँव के उत्साह व लगन को देखते हुए ऊर्जा विभाग द्वारा सोलर पैनल व जनपद खनिज कोष के द्वारा लिफ्ट ऐरीगेशन भी किया गया। उन्नति की कड़ी में आगे पंचायत की ओर से नंदन फल उद्यान योजना की तरफ से 20 एकड़ में सामूहिक वृक्षारोपण भी किया गया।

बर्रा जमीन की सब्जी हार में बदला_समूह से उन्नत्ति

ये कहानी हैं सरस्वती और गोंडवाना समूह स्वयं सहायता समूह की हैं जिन्होंने सामूहिक खेती में सफल प्रयास किया, जो आज गांव में आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुके हैं। समय के साथ इन्होने समाज में पितृसत्ता के बने नियमो को तोड़ा भी। समूहके 6 आदिवासी महिला किसान लक्ष्मी, सिया, सपुरा, प्रमिला, रामवती व द्रोपदी ने वर्ष 2019 में ऊर्जा विकास विभाग द्वारा संचालित योजना के जरिये अपने खेतों के पास के नाले को लिफ्ट सिंचाई से जोड़ा। पहले वो अपने खेतो के धान से साल भर का खाने का और उसको बेचकर बाकी खर्चो को चला पाती थी। शुरुवात में 5 एकड़ में सब्जी लगाई, जिसमे 33,000 की कमाई की।

उसके बाद गाँव योजना निर्माण के द्वारा 20 एकड़ के बर्रे में आम का वृक्षारोपण किया गया। दीदी बताती हैं कि अब वह उसी 15 एकड़ बर्रे हिस्से में सब्जी भाजी के साथ साथ अलग अलग तरह की फसलें जैसे गेहूं, चना सरसो इत्यादि को लगाया। उनका कहना है कि हमने इस वर्ष लॉकडाउन में भी सारे मार्केटिंग चैनल बन्द होने के बावजूद सयुंक्त रुप से 40-50 हज़ार की कमाई की।

आम का बगीचा - एक नया आशियाना

गाँव के लोग आजीविका के लिए क्या करते है? खेती। सामान्यता यही उत्तर सुनने को मिलता है। पर जब परसवाड़ा ब्लॉक के एक समूह की दीदी से बात की तो उन्होंने कुछ अलग उत्तर दिए, भैया हम तेंदू पत्ता चुनते है, महुवा बिनते है, हर्रा सुखाते है और दूसरों के यहां मजूरी करते हैं। दीदी बताती है हमारे यहां की जमीन पथरीली है और वैसे ही एक 5 एकड़ का सामूहिक बर्रा लिया, जहाँ पे मनरेगा के सहयोग से आम्रपाली किस्म के आमों का बगीचा लगाया गया है । दीदी अपने अनुभवों को अत्यंत खुशी के साथ साझा करते हुए बताती है की गत वर्ष उन्होंने आम बगीचे में की सब्जी के माध्यम से 30,000 तक कि आमदनी की और अकेले दम पे अपने घर का खर्च चलाया, वो कहती है कि जब तक पौधे फल देंगे तब तक मैं सब्जी मास्टर बन जाउंगी। आज दीदी गाँव की अन्य महिलाओ के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। और दीदी ने उस बर्रे पड़ी जमीन को अपना नया आशियाना बना लिया हैं।

"जब आम होंगे हम ख़ास होंगे"

संसाधनो में सुधार हमने किये एक साथ

"हम महिला है तो क्या, आगे बढ़ने का कदम हमने साथ में रखा है। बादलाव हमसे शुरु है।"

मध्य प्रदेश की आदिवासी बाहुल्य जिला डिंडोरी के एक छोटा सी गाँव है कुरैली। 2004 से पहले इस गाँव की सभी लोगो की आर्थिक स्थिति काफी ख़राब थी। दीदीयो ने समिति से जुड़कर अपनी गाँव की संसाधानो का संरक्षण एवन सुरक्षा करने का निर्णय लिया। प्रदान संस्था के माध्यम से दीदियो ने आई एन आर एम् के बारे में जाना। दीदियो ने मिलकर अपने गाँव में तालाब, कुँवा, एक खेत सुधार के काम जैसे समतलीकरण के काम का मिलकर प्लान किया। रात भर मीटिंग करने और खेत खेत घूमकर कार्य के प्लान बनाये, फाइलें बनाये, और ग्राम सभा में पारित करवाकर, पंचायत में जमा किये। संसाधनों में सुधार लाने से अभी यहाँ बारो महीने खेती कर रहे है। सब्जी भाजी का धंधा शुरु किये। सालों की मेहनत के बाद अब लोगो का पलायन में नहीं जाना पड़ता है। घर की आर्धिक स्थिति में बदलाव आया है।

संसाधन सखियाँ

महिलाओ के नेतृत्व में गाँव की प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं सुधार लाने के मुख्य उद्देश से समनापुर ब्लाक में आई एन आर एम् की एक महिला दल तैयार हुआ है । संसाधन सखियों का 5 चरणों में प्रदान संस्था ट्रेनिंग दे रही है। हर गाँव के ग्राम संगठन के द्वारा दो दीदियो को इस पद के लिए का चयन किया गया है जिन्हें ट्रेनिंग के द्वारा आई एन आर एम् के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है जिससे वे गाँव में प्लान बनाने से लेकर, प्रस्ताव पारित करवाना और रोज़गार गारेन्टी के तहत काम की निगरानी एवं क्वालिटी की परख कर पाए। ये महिलाये समाज के रुढ़िबद्ध तरीको को चुनौती देते हुए पंचायती राज संस्थानों, महिला समितियों एवं गाँव के अन्य निवासियों के साथ मिल-जुलकर लोगो की मानसिकता एवं भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों में सुधार लाने के लिए एक जुट होकर काम कर रही है। आज समनापुर में 15 दिदिया कुल 22 गाँव के कार्य योजना बनाने, कार्य की स्वीकृति दिलाने में एवं गाँव में संसाधनों की सुधार हेतु खेत तालाब, वृक्षारोपण, 30x40 मॉडल आदि बनाने के कार्यो को देख रही है।

ग्राम संघठन की ताकत से गाँव का नियोजन

"हमने योजना बनायी है जिसमें हर परिवार एक खेत तालाब की माँग पंचायत से की है... कुल 38 खेत तालाब बनाने का प्रस्ताव पारित की है ग्राम सभा ने"

दुधेरा समनापुर ब्लॉक में स्थित एक आदिवासी बाहुल्य गाँव है। लगभग 84 में से 60 परिवार महिला संगठन से जुड़े है, और गाँव के विकास में इस संगठन के महिलाओं का विशेष योगदान रहा है। 2020 में महिला संगठन ने अपने आजीविका बढ़ाने के साथ साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों को बेहतर करने का एक धारणीय योजना बनाएँगे। प्रदान संस्था के मदद से INRM के संकल्पना को समझे और सभी लोग मिलकर इस योजना को सफ़ल करने के 4 दिन में अपने गाँव का योजना तैयार किए। सभी परिवारों ने अपने लिए एक खेत तालाब बनवाने का निर्णय लिया ताकि एक पेच में लगातार खेत तालाब बने। पौधा रोपण, स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच और 30X40 मॉडल के साथ 52 खेत तालाब का योजना बनाए। ग्राम पंचायत ने महिला संगठन की इस पहल की सराहना की।

चंद्रकली की कहानी

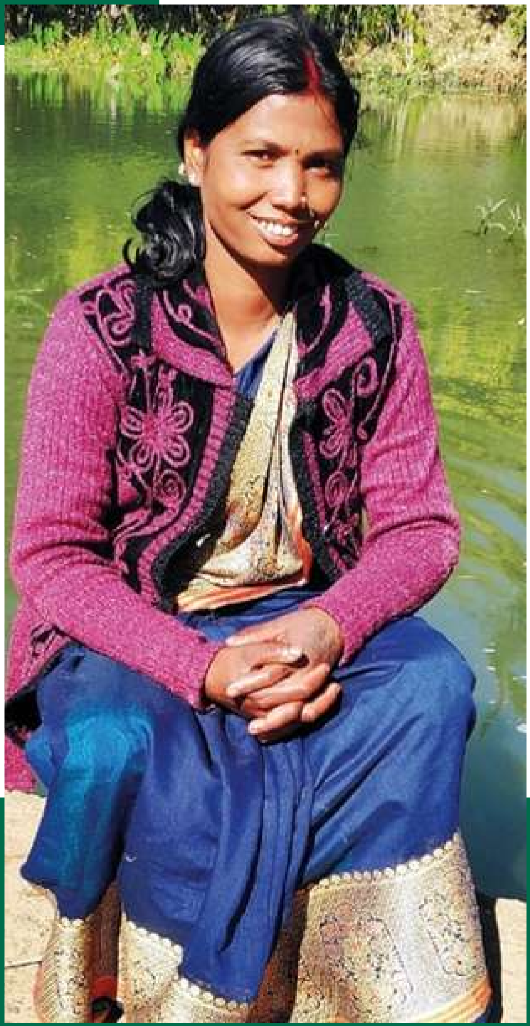

मध्यप्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला डिंडोरी के एक छोटे से गांव कुरैली विकासखंड समनापुर की रहवासी है चंद्र कली मरकाम जिनके अपने होसले से ना केवल खुद को और अपने परिवार को आगे बढ़ाया , बल्कि अपने आसपास के सैकड़ों आदिवासी महिलाओं को मुर्गी पालन गतिविधियों द्वारा गरीबी और पुरुष प्रधानता के कुचक्र से बाहर निकाला।
चंद्रकली ने अपने गांव की महिलाओं को प्रेरित कर रानी दुर्गावती महिला मुर्गी पालन सहकारिता समिति मर्यादित डिंडोरी की शुरुआत की। इसमें आज कुल 24 गांव की कुल 474 आदिवासी एवं दलित महिलाएं शामिल हैं। 2018-19 में सभी महिला उत्पादकों ने 13. 67 करोड़ का कारोबार किया और सदस्यों ने 1. 29 करोड़ का लाभ अर्जित किया । उत्कृष्ट कार्य के लिए कॉपरेटिव को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय पुरस्कार उत्कृष्टता एवं श्रेष्ठता 2018 के द्वितीय पुरस्कार श्रेष्ठता से सम्मानित किया । चंद्रकली को सीआईआई फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष वुमन एग्जांपलर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया।

महिला सरपंच

गाँव के सभी लोगो के साथ मिलकर हमने पानी की समस्या को दूर करने के लिए कार्ययोजना बनाये जिसके तहत हर घर में पीने के पानी के साथ ही 22 खेत तालाब, वृक्षारोपण और मेढ़ बांध का योजना तैयार किए जिसमें से पहले साल में ही 3 खेत तालाब और 8 मेढ़ बांध का काम हुआ। पीने की पानी की व्यवस्था के लिए पंचायत के माध्यम से समूह के सदस्य और मैं, मिलकर PHE वि भाग के मदद से बोर वेल बनवाए।

समूह के महिलाएँ एकजुट होकर बम्हनी बाज़ार को एक वित्तीय वर्ष के लिए खरीदी भी की ताकि पुराने ठेकेदार कि बदसलूकी गरीब दुकानदारों को और ना सहना पड़े। इन सब काम में प्रेरित करने के लिए, इस पद में आने के बाद मेरे सामने कई चुनौतियाँ आयी और मैंने भी धीरे धीरे सीखा के गाँव के विकास के लिए पंचायत में कैसे काम कर सकते है, इससे मेरी हिम्मत बढ़ी और निडरता से काम करती रही। इस पूरी सफ़र में संगठन ने मेरा बहुत साथ दिया।

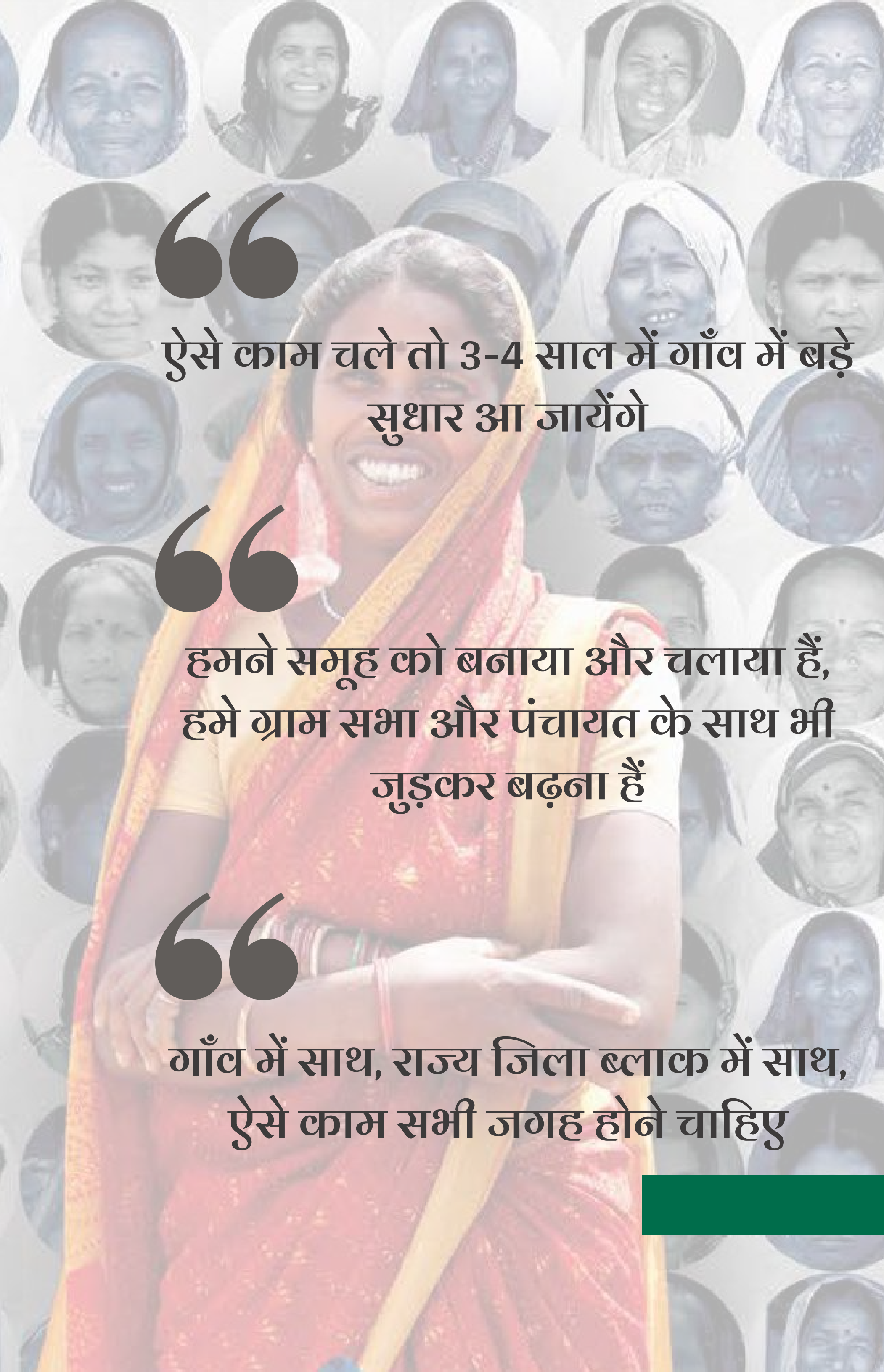

ऐसे काम चले तो 3-4 साल में गाँव में बड़े सुधार आ जायेंगे

हमने समूह को बनाया और चलाया हैं, हमे ग्राम सभा और पंचायत के साथ भी जुड़कर बढ़ना हैं

गाँव में साथ, राज्य जिला ब्लाक में साथ, ऐसे काम सभी जगह होने चाहिए

तुम्हारा काम, हमारा काम नहीं, हम सबका काम एक सोच और नजर, तालमेल से हो

अधिकार मांगने के साथ साथ उसकी जिम्मेदारी उठाना भी जरूरी हैं

ऐसे काम चले तो 3-4 साल में गाँव में बड़े सुधार आ जायेंगे

सवाल पूछना, निरन्तर कोशिशे और आपसी तालमेल जो सोच और कार्य योजना से जुड़कर बढे तो पिछड़े से पिछड़ा गाँव सुधर सकता हैं

नरेगा को हम केवल मजदूरी नहीं मानते ये हमारे लिए उससे बढ़कर हैं...हम वैसे ही इसे लागु करेंगे

हमे पंचायत से अब डर नहीं लगता..उन्हें लगने लगता हैं कभी कभी...डर नहीं साथ चाहिए

हमने देखा हैं की, नरेगा में कार्य योजना बनाकर बढ़ने से जो समझ पिछले 10 सालो से नहीं बनी थी वो एक साल में लोगो की बन गयी

नरेगा के काम हमारी जरूरत और समय के हिसाब से हुआ हैं तब से गाँव में अच्छा काम होने लगा हैं

लघु सीमांत किसान हेतु उपयोगी कार्यो की प्रगति की तस्वीर (सिमित चुने हुए पूर्ण कार्यो के आधार पर) जानकारी स्त्रोत्त: नरेगा कार्यालय, भोपाल (म.प्र.)

कार्य प्रकार	शुरुवात से	वर्ष 19-20	वर्ष 20-21
जल निकासी नाली/मोड़ नाली/ फिल्ड चैनल निर्माण	9331	373	1145
जैविक खाद	396	40	118
सूअर पालन घर	74	10	35
मुर्गी पालन घर	3299	217	630
गौ शाला	88977	392	1750
बकरी पालन घर	13589	118	356
वृक्षारोपण	237322	22626	45244
चेक डैम / स्टॉप डैम	333678	10205	24531
ट्रेंच कार्य	69414	3138	8258
मेड बंधान कार्य	163569	18204	57573

कार्य प्रकार	शुरुवात से	वर्ष 19-20	वर्ष 20-21
गैबियन कार्य	7199	512	1320
पत्थर बाँध / नाला बाँध	22542	2038	8598
नहर/कैनल निर्माण	591	56	251
कुआँ निर्माण	311874	24895	32091
रिसाव टैंक / तालाब	27878	1304	4519
रिचार्ज पिट	12457	1117	6446
घास भूमि विकास	459	79	138
जमीन सुधार	496345	14689	31098
नर्सरी निर्माण	1942	309	686
जमीन सुधार (सीढीनुमा)	4221	367	2638
लिफ्ट सिंचाई	141	1	4
नाडेप / केंचुआ खाद टांका	75469	5605	15658
खेत तालाब	303027	10891	21689

सतत विकास लक्ष्य 17: लक्ष्य हेतु भागीदारी

लक्ष्यों क्रियान्वयन के साधनों को सशक्त करना और सतत विकास के लिए परस्पर साझेदारी को नई शक्ति देना

सम्भावनाये

यही वह पक्ष है जो अन्य सभी 16 लक्ष्यों के बारे में हमारे प्रयासों को एकजुट करती है। एक महत्वाकांक्षी और परस्पर जुड़े हुए विकास एजेंडा के लिए नई भागीदारी आवश्यक है। एक जिला स्तर पर संभावित कार्यो (जो सतत विकास लक्ष्यों में आते हैं) का आंकलन जोड़कर अगर देखा जाए तो निम्न बदलाव राज्य में हो सकेंगे जो की देश के स्तर पर तय विकास लक्ष्यों में मजबूती देंगे।

गरीबी उन्मूलन (आजिवीका संवर्धन और सुरक्षा)

- अनुमानित एक जिले में 50 हजार से अधिक परिवार आजिवीका की मजबूती कर सकते हैं
- औसत आमदनी को दो से तीन गुणा तक बढ़ाया जा सकता हैं

जल संग्रहण

- एक जिले में 3 करोड़ घन मीटर पानी बचाया / संवर्धित किया जा सकता हैं
- सुरक्षित जल कृषि, घरेलु उपयोग आदि के लिए काम में लाया जा सकेगा

प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन

- जल जंगल जमीन में परप्सपर बेहतर प्रबंधन होने से संसाधनो का उचित उपयोग होगा
- गुणवत्ता पूर्ण काम होने से कार्यो में लगभग 25% बजट की बचत होगी जो और अधिक कार्यो में खर्च हो सकेगा

जलवायु सुधार (कार्बन पृथक्करण एवं मिट्टी कटाव पर रोक)

- 10 लाख टन कार्बन पृथक्करण प्रति वर्ष एक जिले में हो सकेगा
- मौसम की अनुकलता बेहतर हो सकेगी

लैंगिक समानता

- महिलाओ को आर्थिक - सामाजिक एवं राजनैतिक मजबूती के होने से लैंगिक असमानताओ में कमी आ सकेगी
- विकास प्रक्रियाओ में बेहतर सामंजस्य और जन भागीदारी हो सकेगी

धन्यवाद

प्रदान Pradan
PROFESSIONAL ASSISTANCE FOR DEVELOPMENT ACTION